Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 3, Issue 1 - 2018

भारत में नकद विहीन लेन देन: स्थिति, चुनौतियां एवं अवसर

कन्हैया लाल*

शोध सार (Abstract)

भारत में विमुद्रीकरण की घटना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं! नकद-विहीन लेन देन (कैशलेस) भी उन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है! नकद-विहीन लेन देन को समझने की दिशा में यह पत्र लिखा गया है! इस पत्र में सर्वप्रथम नकद-विहीन लेन देन का प्रारंभिक परिचय दिया गया है, जिसमें नकद-विहीन लेन देन का अर्थ एवं उसके माध्यम बताए गए हैं! फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में इसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है! इसके पश्चात भारत में नकद विहीन लेन देन की चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया है! एवं पत्र के अंत में नकद-विहीन लेनदेन की भारत में भावी संभावना को तलाश करने का प्रयास किया गया है!

सूत्रशब्द: विमुद्रीकरण, अर्थव्यवस्था, नकद-विहीन लेन देन!

नकद-विहीन लेनदेन का प्रारंभिक परिचय

नकद-विहीन लेनदेन (कैशलेस) का अर्थ

नकद रहित लेन देन अर्थात बिना नकद के वस्तुओं एवं सेवाओं का आर्थिक लेन-देन होता है! दूसरे शब्दों में नकद विहीन लेन देन से आशय उन समस्त व्यवहारों से है, जिसमें वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए भुगतान के रूप में नकदी का प्रयोग नहीं किया जाता! अर्थात क्रेता एवम विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं को नकद रहित रूप में लेनदेन करते हैं तथा नकदी के स्थान पर इन लेनदेन में चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि की सहायता से भुगतान किया एवं पाया जाता है!

नकद विहीन लेन देन कैशलेस के माध्यम

भारत में नकद-रहित लेन-देन के कई माध्यम है! जिसमें से कुछ प्रमुख माध्यम निम्नलिखित है:-

1. चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा भुगतान
2. प्लास्टिक मनी
3. नेट बैंकिंग
4. मोबाइल वॉलेट
5. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
6. यूएसएसडी तकनीक द्वारा भुगतान
7. पेमेंट बैंक द्वारा भुगतान
8. माइक्रो एटीएम द्वारा भुगतान

*व्याख्याता, वाणिज्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर!
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

भारत में कैशलेस की वर्तमान स्थिति

नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था में कैशलेस का सुनहरा भविष्य लेकर आया है! नोटबंदी की वजह से डिजिटल लेनदेन में लोगों की भागीदारी बड़ी है! वर्तमान में भारत में कैशलेस लेनदेन की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- गत 2 वर्षों में बैंकों में नये खातों में तेजी से वृद्धि हुई है! जिसका असर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर भी दिख रहा है! देश में अभी 65 करोड़ के आसपास डेबिट तथा कार्ड ढाई करोड़ के पास क्रेडिट कार्ड है! जिसकी वजह से डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के व्यवहारों में भी वृद्धि देखने को मिली है!
- वर्ष 2015- 16 में डेबिट कार्ड से 1.6 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे, जो बढ़कर वर्ष 2016-17 में 3.3 लाख करोड़ हो गए! इसी प्रकार क्रेडिट कार्ड से वर्ष 2015 -16 में 2.4 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए, जो वर्ष 2016- 17 में बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपए हो गए है! इस प्रकार डेबिट कार्ड में दुगनी से भी अधिक वृद्धि देखी गई है!
- ई-वॉलेट: नोटबंदी के दिन तक रोजाना 17 लाख लेनदेन ई-वॉलेट से हो रहे थे! एक ही महीने में इनकी संख्या बढ़कर 63 लाख हो गई!
- पेमेंट बैंक यथा भारती एयरटेल, वोडाफ़ोन इंडिया, आईडिया सेलुलर इत्यादि में 40 से 50 % वृद्धि का अनुमान है!
- गत 1 वर्ष में ऑनलाइन पेमेंट 57 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है! जबकि डिजिटल पेमेंट लगभग 13 % की दर से बढ़ रहा है!
- POS मशीनों की मांग लगभग दुगनी हो गई है जोकि डिजिटलीकरण में वृद्धि का संकेत है!
- यूपीआई के जरिए होने वाला लेनदेन जनवरी 2017 में 4.2 मिलियन था जो बढ़कर सितंबर 2017 में 30 मिलियन हो गया!
- ई वॉलेट के ऐप डाउनलोड में तीव्र वृद्धि देखि जा रही है अकेले PAYTM ऐप डाउनलोड में 300 % की वृद्धि देखी गई है!

नकद-विहीन लेन देन (कैशलेस) के लाभ

भारत में कैशलेस व्यवस्था को सरकार बढ़ावा दे रही है तथा सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है! स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यकम में इसका जिक्र भी किया था! कैशलेस व्यवस्था के निम्नलिखित फायदे है:-

1. कैशलेस लेनदेन में प्रत्येक व्यवहार का डाटा प्रमाण रहता है! जिससे टैक्स चोरी करना मुश्किल कार्य है! अतः कैशलेस टैक्स चोरी में कमी करके राजस्व में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो रही है!
2. नकद आधारित अर्थव्यवस्था में काला धन के सृजन की पर्याप्त संभावना विद्यमान होती है, जबकि कैशलेस के जरिए किए गए व्यवहारों से ब्लैक मनी समाप्त हो रही है!
3. कैशलेस में प्रत्येक व्यवहार का रिकॉर्ड रहता है! अतः सरकार आसानी से जब चाहे तब इन व्यवहारों की जांच कर सकती है, नतीजन कैशलेस भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में भ्रष्टाचार रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती है!
4. कैशलेस के कारण करेंसी को ज्यादा मात्रा में जारी किये जाने की जरूरत नहीं पड़ती अतः कैशलेस के कारण करेंसी निर्गमन की लागत में कमी आ सकती है!
5. कैशलेस व्यवस्था समाज में वित्तीय समावेश को बढ़ाती है! भारत में छोटी जगह पर जहां बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मोबाइल बैंकिंग, ई पेमेंट की पहुच आसान है! डिजिटल ढ़ाचा तैयार करके बैंकिंग सुविधा को सर्व व्यापी बनाया जा सकता है!

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

6. **नकदी का अधिक प्रचलन, काला धन, एवम जाली नोट के कारण आतंकी और नक्सली घटनाओं को बढ़ावा मिलता है! इसकी सहायता से इन पर भी लगाम लगाना आसान हो जाता है!**
7. **कैशलेस व्यवस्था की वजह से सरकार को जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की दक्षता में वृद्धि प्रतीत होती है! क्योंकि कैशलेस के कारण बिचौलियों की जगह सीधे जनता को धन का हस्तांतरण होता है जिससे आम जनता के कल्याण में वृद्धि हुई है!**

भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में कैशलेस के समक्ष चुनौतियां

भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है! जिसकी आधी से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण परिवेश वाली है! जहां संचार क्रांति अभी विकास अवस्था में है! ऐसे देश में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देना स्वयं में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है! भारत में कैशलेस व्यवस्था के विकास में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:-

1. **भारत गांवों का देश है! जहां की अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है! कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है तथा भारतीय कृषि एक नकद आधारित व्यवसाय है! कृषि में बुवाई से लेकर फसल कटाई तक सारी क्रिया नकदी प्रधान है! ऐसे परिदृश्य में कैशलेस लागू करना भारतीय कृषि के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है! भारत के अधिकांश कृषक अनपढ़ या साक्षर होते हैं अतः उनके लिए तकनीक का इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है! नतीजन कृषि क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट की वृद्धि दर काफी धीमी रही है! साथ ही नकदी के अभाव में कृषक वर्ग को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है**
2. **कैशलेस इकोनॉमी के संबंध में सबसे चिंताजनक मुद्दा साइबर सुरक्षा है! समय के साथ-साथ ऑनलाइन सुरक्षा के संबंध में चिंताएं भी बढ़ती जा रही है! कार्ड की क्लोनिंग, पिन चोरी हो जाना अब आम बात हो गई है! अब हेकिग से बल्क में डाटा चोरी होना तथा रैनसमवेयर जैसे खतरे भी पैदा हो गए हैं! कॉल सेंटर, बैंक इत्यादि जगह भी डाटा सुरक्षित नहीं है! अक्टूबर 2016 में 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा में सेंध हमारी साइबर सुरक्षा में कमजोरी को स्पष्ट दर्शाता है! आजकल साइबर सुरक्षा कानून की सख्त जरुरत है! साथ ही प्राइवेसी कानून का भी अभाव है!**
3. **भारत में कैशलेस की दिशा में एक बड़ी चुनौती नेटवर्क की समस्या भी है! आंकड़े बताते हैं कि भारत में नेटवर्क की गति काफी धीमी है! भारत में पेज लोड होने का औसत समय 5.5 सेकंड है! जबकि चीन में यह समय 2.67 सेकेंड, श्रीलंका में यह समय 4.5 सेकंड तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश में यह समय 4.9 सेकंड है! स्पष्ट है कि भारतीय नेटवर्क काफी धीमा है! अधिकांश कैशलेस लेनदेन करने हेतु अच्छी स्पीड की जरूरत रहती है! लेकिन भारत में इंटरनेट की धीमी गति होने के कारण ग्राहकों को सेशन टाइम आउट, पेमेंट हेल्ड, इंटरनेट डिसकनेक्ट, नेटवर्क एरर, ओटीपी का समय पर न मिलना इत्यादि प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है!**
4. **भारत में इंटरनेट की ऊंची लागतें भी कैशलेस इंडिया की राह में चुनौतियां है! भारत में औसतन 1 GB डाटा की लागत 150 रुपए से 200 रूपये (3G) पडती है! जो की बहुत ज्यादा है!**

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

5. भारत एक तरफ तो कैशलेस को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकार कैशलेस के प्रति नकारात्मक वातावरण बना रही है! कार्ड से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाना, पेट्रोल की खरीद कार्ड से करने पर अतिरिक्त शुल्क वसूलना, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग पर शुल्क लगाने की सरकारी नीतियां स्वयं कैशलेस को असफल बनाने पर तुली है!
6. कैशलेस लेनदेन हेतु आम तौर पर इंटरनेट व स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ती है! आंकड़े बताते हैं कि भारत में मात्र 27 फ़ीसदी आबादी के पास इंटरनेट है तथा मात्र 17 फ़ीसदी लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है! इन आंकड़ों से भारत में कैशलेस का भविष्य उज्जवल प्रतीत नहीं होता!
7. समय-समय पर किए गए सर्वे से यह बात सामने उभरकर आई है कि भारत में कैशलेस के लेन-देन बड़े जरूर है! लेकिन भारत में कैशलेस लेनदेन केवल बड़े शहरों तक सीमित रह रहा है! गांव की अर्थव्यवस्था आज भी नकद प्रधान है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार का कमजोर कमजोर ढ़ाचा भी इसके लिए जिम्मेदार है ! दूसरी तरफ बड़े शहरों में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जो की नकद आधारित प्रणाली पर ही कार्य करते हैं, अतः कैशलेस व्यवस्था पूर्णतया सफल नहीं रह पाई है!
8. भारत की आबादी की प्रकृति के अनुरूप भारत में कैशलेस को सफल बनाने के लिए पोस मशीनों का काफी अहम भूमिका हो सकती है! लेकिन व्यवहारिक धरातल पर सिथति एकदम विपरीत है! भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर महज 856 पीओएस मशीनें उपलब्ध है! इस हकीकत के साथ भारत कैशलेस बनेगा यह सोचना भी स्वयं में हास्य हास्यास्पद लगता है! बिना पर्याप्त तैयारी तथा आधी अधूरी जानकारी के कारण भारत में कैशलेस व्यवस्था महज औपचारिक एवं मजाक बनकर रह गई है!

भारत में नकद-विहीन लेन देन (कैशलेस) का भविष्य

समय नित्य नया रूप बदलता है! वस्तु विनिमय प्रणाली के दौर से लेकर आज तक मुद्रा ने न जाने कितने ही रूप परिवर्तित किए हैं! कल तक बटुए में रखी जाने वाली मुद्रा आज डिजिटल रूप में हम सब के मोबाइल में आ चुकी है! भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन कैशलेस की दिशा में अग्रसर जरूर हो रहा है! पहले जहां प्रत्येक लेनदेन नकद में ही होते थे, अब छोटी-छोटी लॉरियों पर भी पेटीएम से भुगतान स्वीकार करना भारत में बदलाव का प्रतीक है! अब दूरसंचार कंपनियां छोटे शहरों और गांवों की तरफ पलायन कर रही है! भारतीय बैंक इंटरनेट ऐप के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं! इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में लगातार वृद्धि दृष्टिगत हो रही है! जियो आने के बाद संचार क्रांति में एक नए युग का प्रारंभ हुआ है! भारत में कैशलेस की दिशा में अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपाय व मापदंड अपनाए जा रहे हैं!

प्रीपेड कार्ड, डिजिटल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि में तीव्र गति से वृद्धि होना ये सभी घटनाए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत मानी जा सकती है! साथ ही वित्त मंत्रालय की तरफ से कैशलेस को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा रही है! इसके अलावा विविध प्रकार की छूट का ऐलान भी किया जा रहा है! जिससे इसकी रफ्तार में तेजी आने की उम्मीद है! भारत का ई कॉमर्स बाजार तेज गति से बढ़ रहा है! अतः कुल मिलाकर यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय भारत में कैशलेस का बेहतर भविष्य लेकर आएगा, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है!

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में फिलहाल कैशलेस व्यवस्था इतनी तेज गति से नहीं बढ़ पाई है, जिस गति से इसे बढ़ना चाहिए था। लेकिन कुछ बुनियादी कमजोरियों को दूर करके भारत कैशलेस इंडिया बन सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र: राजस्थान
[2]. राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान।
[3]. राजस्थान पत्रिका।
[4]. दैनिक भास्कर।
[5]. दैनिक नवज्योति।
[6]. www.wikipedia.com.
[7]. www.drishtiias.com/hindi/current-affairs/digital-payment.
[8]. http://www.livemint.com/opinion.
[9]. http://editorial.mithilesh2020.com/cashless.
[10]. www.google.co.in.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**